# International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)

Volume 6 Issue 6, September-October 2022 Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470

# भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समीक्षात्मक अध्ययन

# डॉ. सुरेन्द्र सिंह चारण

एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय महाविद्यालय, दौसा, राजस्थान

सार

प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद आय स्तरों की अधिक यथार्थवादी तुलना प्रदान करता है क्योंकि यह किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद को उस देश की जनसंख्या से विभाजित करता है। भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम बनी हुई है, वर्ष 2021 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 190 देशों में से 122वें स्थान पर है। सामान्यता भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में यह कहा जाता है - '' भारत एक धनी देश है , किन्तु यहाँ के निवासी निर्धन है। '' वास्तव में यह कथन विरोधाभास की स्थिति को व्यक्त करता है। देश धनवान है किन्तु लोग गरीब है। यदि भारत की प्राकृतिक सम्पदा एवम् मानवीय साधनों पर विचार किया जाय तो यह कथन सही है कि भारत एक धनी देश है। प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता के ही कारण भारत को ' सोने की चिड़िया ' कहा जाता था। किन्तु यहाँ के निवासियों के जीवन स्तर कुपोषण , रूगणता , विपन्नता के कारण ही यह कहा जाता है कि यहाँ के निवासी गरीब है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत अनेक प्रयास किए गए है और इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था में देखने को भी मिला रहा है। भारत ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन किए है। उदाहरण के लिए कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति को अपनाए जाने से देश में खाद्यान्न के क्षेत्र मे आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। उद्योग के क्षेत्र में आधारभूत एवं भारी उद्योगों की स्थापना की गयी है और भारत विश्व के 10 बड़े औद्योगिक राष्ट्रो के अन्तर्गत आता है। नियोजित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हुआ है। बैंक , बीमा , कम्पनियों , दूरसंचार , डाकसेवा , यातायात के साधनों में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। इससे प्रतिव्यक्ति आय , बचत , एवं निवेश की दरों में भी वृद्धि हुई है। इससे यह प्रतीत होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर की गति धीमी है परन्तु सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सतत् प्रयासरत है।

How to cite this paper: Dr. Surendra Singh Charan "Critical Study of Indian Economy in Present Perspective"

Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-6 | Issue-6, October



2022, pp.1949-1955, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd52193.pdf

Copyright © 2022 by author(s) and International Journal of Trend in Scientific Research and Development

Journal. This is an Open Access article distributed under the



terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

वर्तमान में सरकार ने देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 34 लम्बित सड़क और कई रेल परियोजनाओं को फिर से चालू करने तथा कोल इण्डिया लिमिटेड में 10 प्रतिशत का निवेश एवं निर्यातकों को सस्ती पूँजी उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है।

कोविड-19 संकट आने के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था नॉमिनल जीडीपी के आधार पर 45 साल के न्यूनतम स्तर पर रही भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड के उपरांत अत्यंत संकटग्रस्त स्थिति में है। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन की आवश्यकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति:-

- भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद भले ही कृषि क्षेत्र हो परन्तु, वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास के पीछे मिडिल क्लास और लोअर मिडल क्लास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ परम्परागत समस्याएं हैं यथा निम्न प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक असमानता, कृषि पर भरी दबाव तथा कृषि का पिछड़ापन अत्यधिक जनसंख्या दबाव बड़े पैमाने पर बेरोजगारी इत्यादि।

कोविड-19 संकट आने के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था नॉमिनल जीडीपी के आधार पर 45 साल के न्यूनतम स्तर पर थी। रियल जीडीपी के आधार पर 11 साल के न्यूनतम स्तर पर थी। परन्तु कोविड-19 द्वारा जारी वैश्विक संकट ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख नए संकट को उत्पन्न किया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख चुनौतियाँ:-गिरती जीडीपी:-

वर्तमान की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक गहरी संकट की तरफ बढ़ रही है। विभिन्न प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के संदर्भ में जो आकलन जारी किए हैं, वे चिंताजनक हैं। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी और मूडीज जैसी संस्थाओं ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में एक बड़ी कटौती की है। आईएमएफ के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर 1.9 फीसदी रह सकती है.

रिवर्स माइग्रेशन:-

 इन सभी समस्याओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था "रिवर्स माइग्रेशन" को भी देख रही है। अंतर्राजीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रिवर्स माइग्रेशन के फलस्वररूप आर्थिक गतिविधियों पर संकट उत्पन्न हो गया है। अमेरिका में एच 1 बी बीजा के नियमो में परिवर्तन भारत के लिए हितकर नहीं हैं। ऐसी स्थिति में रेमिटैन्सेस के घटने की भी सम्भवना है।

#### रोजगार पर असर

- भारत के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (सीएमआईई) के जारी आंकड़ों के अनुसार, लॉकडाउन की वजह से कुल 12 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। कोरोना संकट से पहले भारत में कुल रोजगार आबादी की संख्या 40.4 करोड़ थी. जो इस संकट के बाद घटकर 28.5 करोड़ हो चुकी है।
- फिलहाल डब्लूएचओ की मानें तो कोविड-19 के संकट का अभी सबसे बुरा दौर आना बाकी है।

#### ग्रामीण अर्थव्यवस्था:-

अंतर्राजीय रिवर्स माइग्रेशन के कारण कृषि पर दबाव बढ़ गया है ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। प्रवासी श्रमिकों के बेरोजगार हो जाने के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र मे मांग भी कम हुई है। इस प्रकार की स्थिति ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है।

#### अन्य आर्थिक प्रभाव:-

इसके साथ ही साथ शिक्षा, जिम, पर्यटन, ट्रांसपोर्ट की गतिविधियां भी रुकी रहीं जिन्होंने आर्थिक समस्या को अत्यंत गंभीर कर दिया है। इससे बिभिन्न प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार समाप्त हो गए।

#### वैश्विक कारक:-

अमेरिका चीन की व्यापारिक जंग तथा भारत चीन की व्यापारिक जंग भी अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है।

# भारत के सम्मुख नए अवसर:-

- चीन द्वारा वायरस के प्रसार के चर्चा के मध्य कई कंपनियों ने चीन से भारत की तरफ पलायन किया है।
- भारत सरकार द्वारा आत्मिनभरता का प्रयास देश की अर्थव्यवस्था को स्वसक्षम बनाने में सहायक होगा।
- कृषि तथा फार्मासूटिकल उद्योग इस समय भी वृद्धि दर्ज कर रही हैं। कई वर्षो उपरांत ऐसा पहली बार हुआ है कि देश की जीडीपी तो गिरावट दर्ज कर रही है परन्तु कृषि गतिविधियों ने वृद्धि दर्ज की है।
- तकनीकी यथा ऑनलाइन शिक्षा , टेलीमेडिसिन ,जैसी गतिविधियों ने न सिर्फ लॉक डाउन में आर्थिक गतिविधियों को गति दी है वरन डिजिटल इंडिया की संकल्पना को भी बल दिया है।

#### आगे की राह

भारत की आर्थिक स्थिति निस्संदेह ख़राब अवस्था में चल रही है, परन्तु इसमें सुधार किया जा सकता है। विश्व बैंक के अनुसार यदि भारत नीतिगत सुधार करने में सफल होता है तो देश की अनुमानित 2% वृद्धि की अर्थव्यवस्था 4 % तक बढ़ सकती है।

इस दृष्टिकोण से भारत को एक वित्तीय परिषद की आवश्यकता है जो इन विषयों से सम्बंधित निर्णय ले सके। इसके साथ साथ

रिज़र्व बैंक को अपनी भूमिका में आना होगा। देश में नकदी का प्रवाह बढ़ाना होगा। परियोजना निगरानी समूहों का गठन होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय निवेश पर तत्काल निर्णय ले सके। सरकार को एमएसएमई को गति प्रदान करना होगा इस निमित्त सरकार बिभिन्न प्रयास कर रही है।

इन्ही प्रयासों के माध्यम से अर्थव्यवस्था का पुनुरुद्धार संभव होगा।

# परिचय

भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रायः विकासशील कहा जाता है। यद्यपि अंग्रेजी शासनकाल की तरह यहां की अर्थव्यवस्था में अब गतिहीनता नहीं है , लेकिन आजादी के बाद भी यहां पर कोई क्रांतिकारी आर्थिक विकास नहीं हुआ है। आर्थिक मामलों के जानकार आलोक पौराणिक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की मिश्रित तस्वीर उभरकर सामने आ रही है। [1,2] उनका कहाना है " आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का तीन स्तरों पर वर्गीकरण हो जाएगा , एक ओर होगें , सर्विसेज सेक्टर , विदेशी निवेश और सेंसेक्स जैसे पहलू ज हाँ माहौल काफी सकारात्मक है। दूसरी तरफ है मध्यम वर्ग की अर्थव्यवस्था जिसमें अपार सम्भावनाएं दिखाई पड़ती है। लेकिन कई तरह की परेशानियां भी है और तीसरे स्तर पर है एक ऐसा वर्ग जिसका ऊपर के दो वर्गी से कोई लेना - देना नहीं है , उनकी समस्याएं शायद वैसी की वैसी रहने वाली है और शायद बढ़ने वाली है " मुलभूत ढांचे में तेज प्रगति न होने से एक बड़ा तबका अब भी नाखुश है और एक बड़ा हिस्सा इन सुधारों से अभी भी लाभान्वित नहीं हुए है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का संकट अभी बरकरार है। कृषि , सेवा , विनिर्माण तथा गैर - टिकाऊ उपभोक्ता क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन से औद्योगि उत्पादन की वृद्धि दर कम रही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था " मुडीज इन्वेस्टर्स सर्विस " ने अपने सर्वे में बताया है कि भारत में आंतकवादी हमलों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर उल्लेखनीय और दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पडा है। भारत में कई जगहों में अब भी सड़क बिजली और पानी जैसी मूलभूत जरूरतों की कमी है और ये तस्वीर सिर्फ गांवो की नहीं है बंगलौर जैसे शहरो की भी है। इन मूलभूत जरूरतों के अभाव में उद्योग ओर सेवा सेक्टर में जारी विकास इतनी ही गति से बरकार रह जाएगा ये भी एक बडा सवाल है। क्रेडिट एजेंसी क्रिसिल के निर्देशक डी. के. जोशी भारत के आर्थिक विकास को प्रसन्नता का प्रतीक बताते है। आधारभूत ढांचे ओर बेरोजगारी जैसी समस्याओं को चिंता का विषय मानते है। [3,4] रोजगार के अवसरों की बात करे तो भारत मे इस समय करीब तीन करोड़ साठ लोख बेरोजगार युवा है। कहने को तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है लेकिन मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 127 है। इससे यह प्रतीत होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर की गति धीमी है परन्तु सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सतत् प्रयासरत है।

वैश्विक संस्था " डॉ. यचे " बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 तक देश का राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद (जी . डी . पी .) का 3.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 2014-15 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.85 प्रतिशत रहा है। वर्तमान में प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद निरंतर जारी सुधारों से देश की आर्थिक दर बढ़ने की पूरी सम्भावना है। वित्तीय घाटा धीरे - धीरे कम किया जा रहा है ओर मंहगाई को भी धीरे - धीरे नियत्रंण में करने की कोशिश जारी है।

वित्तीय सेवा क्षेत्र की प्रमुख कम्पनी " बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच " (बोफा एम . एल .) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था उम्मीद से बहुत कम रफ्तार से सुधार दर्ज कर रही है। लेकिन इतनी तेजी से जरूर आगे बढ़ रही है कि ब्राजिल और रूस को पछाड़कर चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था बनने को तत्पर है।[5,6]

अन्तर्राष्ट्रीय संस्था नोमुरा (nomura) ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय सुधार का दौर जारी है। विकासदर के अलावा अगर आर्थिक प्रगति के दूसरे मापदड़ों की बात करे तो भारतीय अर्थव्यवस्था काफी बेहतर स्थिति में नजर आ रही है।

विचार-विमर्श तालिका 1.1 भारत में क्षेत्रवार सकल मूल्य वर्धित आय वर्ष 2011-12 की कीमतों पर (करोड रू . एवं प्रतिशत में)

क्षेत्र	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	19,32,692	20,67,935	21,72,910	23,82,289
	(18.64)	(18.03)	(17.45)	(17.32)
उद्योग	31,88,270	34,55,221	36,83,358,	38,89,791
	(30.76)	(30.12)	(29,.58)	(29.02)
खनन एवं उत्खनन	2,95,716	3,13,844	2,96,041	3,09,178
	(2.85)	(2.74)	(2.38)	(2.25)
विनिर्माण	17,13,445	18,83,929	20,65,093	22,78,149
	(16.53)	(16.42)	(16.58)	(16.57)
विद्युत,जल,गैस आपूर्ति	2,59,840	2,79,456	3,21,765	3,38,396
	(2.51)	(2.44)	(2.58)	(2.46)
निर्माण	9,19,269	9,77,992	10,00,459	10,64,068
	(8.87)	(8.53)	(8.03)	(7.74)
सेवा	52,45,605	59,47,260	65,95,670	73,78,705
	(50.6)	(51.85)	(52,97)	(53.66)
व्यापार,होटल,	18,74,443	20,95,737	22,94,367	25,38,162
परिवहन संचार	(18.08)	(18.27)	(18.43)	(18.46)
वित्त, बीमा, वास्तविक जायदाद एवं व्यावसायिक सेवाऍ	20,69,386 (19.96)	23,63,328 (20.60)	26,32,432 (21.14)	28,69,300 (21.06)
सार्वजनिक प्रशासन	13,01,476	14,88,595	16,68,871	19,44,243
	(12.55)	(12.98)	(13.40)	(14.14)
G.V.A. योग्	1,03,66,266	1,14,70,415	1,24,51,938	1,37,50,786
	(100)	(100)	(100)	(100)

स्त्रोत – सी.एस.ओ. 2016–17 कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत में हैं।

तालिका 1.2 भारत के सकल मूल्य वर्धित आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान (प्रतिशत में)

क्षेत्र	2013-14	2014-15	2015—16	2016-17	प्रवृति
प्राथमिक क्षेत्र (कषि, सम्बद्ध क्षेत्र एवं खनन तथा उत्खनन)	21.49	20.77	19.83	19.57	घटने की प्रवृति
द्वितीयक क्षेत्र (विनिर्माण)	27.91	27.38	27.20	26.77	घटने की प्रवृति
तृतीयक क्षेत्र (सेवाऍ)	16.53 50.60	16.42 51.85	16.58 52.97	16.57 53.66	बढने की प्रवृति
सकल मूल्य वर्धित आय	100.00	100.00	100.00	100.00	

स्त्रोत — केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन। तालिका 1.3 भारत के सकल मूल्य वृद्धि दर (प्रतिशत में)

क्षेत्र   2013–14   2014–15   2015–16   2016–17						
(पात्र	2013-14	2014—15	2015-16	2016-17		
कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	4.2	-0.2	1.3	4.1		
उद्योग	5.0	5.9	7.4	5.2		
खनन एवं उत्खनन	3.0	10.8	7.4	1.8		
विनिर्माण	5.6	5.5	9.3	7.4		
विघुत ,गैस, जल, आपूर्ति	4.7	8.0	6.6	6.5		
निर्माण	4.6	4.4	3.9	2.9		
सेवा	7.9	10.3	8.9	8.8		
व्यापार,होटल,परिवहन,संचार	7.8	9.8	9.0	6.0		
वित्त, वास्तविक जायदाद एवं सेवाऍ	10.1	10.6	10.3	9.0		
सार्वजनिक प्रशासन	4.5	10.7	6.6	112.8		
सकल मूल्य वृद्धि	6.3	7.1	7.2	7.0		

स्त्रोत - केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन।

स्त्रोत - सी . एस . ओ . एकोनामिक सर्वे भारत सरकार 2016-17 पेज नम्बर 140

<sup>1.</sup> प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के साथ खनन एवं उत्खनन का प्रतिशत जोड़ा जाता है।

<sup>2.</sup> द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग में से खनन एवं उत्खनन का प्रतिशत घटाया जाता है।

नोट - (1) प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के साथ खनन एवं उत्खनन का प्रतिशत जोड़ा जाता है। (2) द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग में से खनन एवं उत्खनन का प्रतिशत घटाया जाता है।[7]

#### परिणाम

तालिका 1.1 एवं 1.2 में देश के क्षेत्रवार सकल मूल्य वर्धित मूल्य को वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 के लिए वर्ष 2011-12 के स्थिर कीमत के आधार पर दिखाया गया है। वर्तमान में देश की आय को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन प्रक्रिया के अन्तर्गत हुए मूल्य - वृद्धि के योग के रूप में मापा जाता है। तालिका से स्पष्ट है कि -

- (अ) कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों का योगदान देश के सकल मूल्य वर्धित आय में वर्ष 2013-14 के 18.64 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2016-17 में 17.32 प्रतिशत हो गया है। इन 4 वर्षी में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के योगदान में 1.32 प्रतिशत की कमी हुई है।
- (ब) उद्योग क्षेत्र का योगदान वर्ष 2013-14 के 30.76 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2016-17 में 29.2 प्रतिशत हो गया है। इसमें भी इन 4 वर्षों में 1.74 प्रतिशत की कमी हुई है। किन्तु विनिर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग स्थिर है। वर्ष 2013-14 में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 16.53 प्रतिशत था जो वर्ष 2016-17 में 16.57 प्रतिशत हो गया है। दूसरी ओर विनिर्माण क्षेत्र के योगदान में कमी आने की प्रवृत्ति है। यह वर्ष 2013-14 के 8.87 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 7.74 प्रतिशत हो गया है।
- (स) सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2013-14 में 50.6 प्रतिशत था जो बढ़कर 2016-17 में 53.66 प्रतिशत हो गया है। इस क्षेत्र के योगदान में सतत् वृद्धि होने की प्रवृत्ति है। देश के सकल मूल्य वर्धित आय में 50 प्रतिशत से अधिक आय सेवा क्षेत्र से प्राप्त हो रही है। यह क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है, केवल सेवायें प्रदान करता है। दूसरी ओर कृषि एवं उद्योग दोनों क्षेत्रों के योगदान में गिरावट की प्रवृत्ति है जो चिन्ताजनक है।[8,9]

प्राथिमक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के अन्तर्गत सकल मूल्य विधित आय की संरचना को देखें तो इसकी प्रवित्त भी विभिन्न क्षेत्रों के योगदान की प्रवृत्ति के समान है। प्राथिमक क्षेत्र में उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। जिनमें वस्तुओं के उत्पादन में प्रकृति का योगदान महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए प्राथिमक क्षेत्र में कृषि, सम्बद्ध क्षेत्रों में पशुपालन, वानिकी एवं मत्स्य पालन को शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, खनन एवं उत्खनन को भी प्राथिमक क्षेत्र में शामिल किया जाता है क्योंकि खनिज पदार्थ भी प्रकृति की देने होते हैं, इसीलिए द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग में खनन एवं उत्खनन को शामिल नहीं किया जाता है। तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है।

तालिका 1,2 मे स्पष्ट है कि -

- (1) प्राथमिक क्षेत्र का योगदान देश के सकल मूल्य वर्धित आय में वर्ष 2013-14 में 21.49 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2016-17 में 19.57 प्रतिशत हो गया है। इसमें 1.92 प्रतिशत की कमी आई है। प्राथमिक क्षेत्र में गिरावट की प्रवृत्ति है।
- (2) द्वितीयक क्षेत्र का योगदान सकल मूल्य वर्धित आय में वर्ष 2013-14 में 27.91 प्रतिशत था जो वर्ष 2016-17 में घटकर 26.77 प्रतिशत हो गया है। इस क्षेत्र में प्रतिशत की कमी आयी है। इस क्षेत्र में इन 4 वर्षों में गिरावट की प्रवृत्ति है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में 1.14 विनिर्माण का योगदान वर्ष 2013-14 में 16.53 प्रतिशत था जो वर्ष 2016-17 में 16.57 प्रतिशत हो गया है। इस क्षेत्र में सामान्यतः स्थिर रहने की प्रवृत्ति है। " मेक इन इंडिया ' का विशेष प्रभाव इस क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ रहा है।

(3) तृतीयक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2013-14 में 50.6 प्रतिशत था जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 53.66 प्रतिशत हो गया है। इस क्षेत्र में सतत् रूप से बढ़ने की प्रवृत्ति है। देश के सकल मूल्य वर्धित आय में सेवा क्षेत्र का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि 50 प्रतिशत से अधिक आय इसी क्षेत्र से प्राप्त हो रही है।

देश के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के वर्ष 2013-14 से 2016-17 में आर्थिक वृद्धि दर को तालिका 1.3 में दिखाया गया है। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2013-14 एवं 2016-17 में आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः 4.2 एवं 4.1 प्रतिशत है किन्तु 2014-15 में यह ऋणात्मक है जबिक वर्ष 2015-16 में वृद्धि दर मात्रा 1.3 प्रतिशत है। उद्योग के क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि दर 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक वृद्धि हुई है जबिक वष्ट्र्य 2016-17 में यह घटकर 5.2 प्रतिशत रह गयी है। सेवा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 की तुलना में अन्य वर्षों में आर्थिक वृद्धि दर ऊँची है किन्तु वर्ष 2014-15 के 10.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में यह घटकर क्रमशः 8.9 एवं 8.8 प्रतिशत हो गया है।[10,11]

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रतिकूल वैश्विक चुनौतियों और परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अभी आगे बढ़ने में कामयाब है। विगत वर्षो में लगातार मानसून की खराब स्थिति एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में नरमी के कारण भारत का निर्यात सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। वर्तमान में मुद्रास्फीति और विदेशी निवेश समेत अर्थव्यवस्था में चैतरफा सुधार परिलक्षित हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र साख्यिकी प्रभाग के राष्ट्रीय लेखों के अनुसार दिसम्बर 2013 के आधार पर की गई देशों की रैंकिंग के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार भारत की रैंकिंग 10 और प्रतिव्यक्ति सकल आय के अनुसार भारत विश्व में 161 वें स्थान पर रही है। देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार में तेजी के साथ रोजगार बाजार भी सकारात्मक नजर आ रहा है।

अंत में कहा जा सकता है। कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। उम्मीद है कि आनेवाले वर्षो में विकासदर और बढ़ेगी। औद्योगि एवं सेवा क्षेत्र में विकास की बदौलत भारत में विकास की गाड़ी तेजी से दौड़ तो रही हैं लेकिन अभी भी उसके सामने कई तरह की चुनौतियां है। चीन जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अनुभव किए जा रहे वित्तीय संकट के बावजूद यह एक निश्चित गति बरकार रखे हुए है। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने हेतु नए सुधारों के ऐजेंडे से भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तथा विदेशी मुद्रा भण्डार भी बढ़ेगा। अतः आज जरूरी हो गया है कि अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए सुधारों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए।

### निष्कर्ष

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक समीक्षा 2021-22 पेश करते हुए कहा कि पिछले वर्ष की महामारी से उत्पन्न मंदी के बाद भरत के विदेशी व्यापार में मजबूती से सुधार हुआ है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार का तेजी से संचय हुआ है। चालू वर्ष के दौरान भारत के विदेशी क्षेत्र की समुत्थान शक्ति (लचीलापन) अर्थव्यवस्था में विकास के पुनरुद्धार के लिए अच्छा संकेत है। हालांकि वर्ष 2022-23 के दौरान कोविड-19 के नये वेरिएंट्स के

साथ वैश्विक तरलता के कड़े होने के घटते हुए जोखिमों और वैश्विक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार अस्थिरता, उच्च माल ढुलाई लागत भारत के लिए चुनौती हो सकती है।[12]

# विदेशी व्यापार प्रदर्शनः

समीक्षा यह दर्शाती है कि वैश्विक मांग में दोबारा वृद्धि के साथ-साथ घरेलू गतिविधि के पुनरुद्धार को देखते हुए भारत के वस्तु (पण्य) आयात और निर्यात में जोरदार उछाल आया है और यह चालू वर्ष के दौरान पूर्व- कोविड स्तरों को पार कर गया है। सरकार द्वारा उचित समय पर की गई पहल से भी निर्यात के पुनरूद्धार में सहायता मिली है। अप्रैल-नवम्बर, 2021 में अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और चीन शीर्ष निर्यात गंतव्य बने रहे जबिक चीन, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़े आयात स्रोत रहे। कमजोर पर्यटन राजस्वों के बावजूद अप्रैल-दिसम्बर, 2021 के दौरान संवाओं से होने वाली निवल आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी ऐसा मजबूत सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक आय के कारण तब संभव हुआ जब आय और भुगतान दोनों ने ही अपने पूर्व-महामारी स्तरों को पार कर लिया था।

आर्थिक समीक्षा यह दर्शाती है कि कैलेंडर वर्ष 2021 की पहली छमाही में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में तेजी देखी गई जिससे वस्तु व्यापार अपने पूर्व-महामारी शीर्ष से भी ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। समीक्षा यह भी दर्शाती है कि भारत के वस्तु निर्यात में वैश्विक रुझान का अनुसरण किया और अप्रैल-दिसम्बर, 2021 के दौरान वस्तु निर्यात में 49.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 2019-20 (अप्रैल-दिसम्बर) की तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह बढ़ोतरी 26.5 प्रतिशत रही थी। समीक्षा में यह उल्लेख किया गया है कि भारत ने वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य का 75 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया है और यह अपना लक्ष्य अर्जित करने के मार्ग पर बेहतर तरह से अग्रसर है। समीक्षा में बताया गया है कि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा के कारण बाजारों में तेजी से हुई रिकवरी, उपभोक्ता व्यय में बढ़ोतरी, बचत और खर्च करने योग्य आय में वृद्धि और सरकार द्वारा निर्यात को जोरदार प्रोत्साहन देने के कारण वर्ष 2021-22 में निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। निर्यात में बढ़ोतरी व्यापक आधार वाली रही है। भारत का कृषि निर्यात लगातार अच्छा चल रहा है। अप्रैल-नवम्बर, 2021 के दौरान कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 23.2 प्रतिशत वृद्धि हुई है। समीक्षा यह सिफारिश करती है कि मुक्त व्यापार अनुबंधों को प्रोत्साहन देने से भारत के निर्यात विविधीकरण के लिए संस्थागत प्रबंधों को उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।[13]

वस्तु आयात के मुद्दे पर आर्थिक समीक्षा यह दर्शाती है कि भारत में घरेलू मांग का पुनरुद्धार हुआ है जिससे मजबूत आयात वृद्धि हुई है। अप्रैल-दिसम्बर, 2021 में वस्तु आयात पिछले साल की इसी अविध की तुलना में 68.9 प्रतिशत की दर से और अप्रैल-दिसम्बर 2019 की तुलना में 21.9 प्रतिशत बढ़ा है और पूर्व-महामारी स्तर को पार गया है। समीक्षा यह दर्शाती है कि भारत के आयात स्रोतों के विविधीकरण में बढ़ोतरी हुई है और यह अप्रैल-नवम्बर अविध में चीन का हिस्सा 17.7 से घटकर 15.5 प्रतिशत होने से परिलक्षित होता है। समीक्षा यह भी दर्शाती है कि वस्तु व्यापार घाटा अप्रैल-दिसम्बर, 2021 में बढ़कर 142.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

# सेवाओं में व्यापार

भारत ने कोविड-19 के बाद की अवधि में विश्व सेवा व्यापार में प्रभावशाली प्रदर्शन जारी रखा है। अप्रैल-दिसम्बर 2021 के दौरान सेवा निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 18.4 प्रतिशत वृद्धि के साथ यह 177.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। समीक्षा यह दर्शाती है कि सेवा निर्यात में मजबूत वृद्धि में सरकार द्वारा चलाये गए प्रमुख सुधारों का भी योगदान है। अप्रैल-दिसम्बर, 2021 में सेवा आयात 21.5 प्रतिशत बढ़कर 103.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

#### चालु खाता शेष

आर्थिक समीक्षा बताती है कि भारत का चालू खाता शेष वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद के 0.2 प्रतिशत घाटे में परिवर्तित हो गया जिसमें मुख्य रूप से व्यापार खाते में घाटे का योगदान है। वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में निवल पूंजी प्रवाह बढ़कर 65.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर रहा ऐसा बाहरी निवेश के लगातार अंतर्प्रवाह, निवल विदेशी वाणिज्यिक उधार, अधिक बैंकिंग पूंजी और अतिरिक्त विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) आवंटन के कारण हुआ। भारत का बाहरी ऋण सितम्बर, 2021 के अंत तक बढ़कर 593.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जो एक साल पहले 556.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा एसडीआर आवंटन के साथ-साथ उच्च वाणिज्यिक उधार से परिलक्षित होता।

# पूंजी खाता

आर्थिक समीक्षा यह दर्शाती है कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में निवल विदेशी निवेश प्रवाह वित्त वर्ष 2021 की इस अविध की तुलना में 25.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर कुछ कम रहा। नवम्बर, 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और सकल एफडीआई प्रवाह मुख्य रूप से कम इक्विटी निवेश के कारण कम रहा। समीक्षा में बताया गया है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेश अस्थिर बना रहा।

# भुगतान संतुलन शेष और विदेशी मुद्रा भंडार

आर्थिक समीक्षा में यह दर्शाया गया है कि मजबूत पूंजी प्रवाह सामान्य वर्तमान लेखा घाटे के वित्त पोषण के लिए पर्याप्त था जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में 63.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल भुगतान संतुलन अधिशेष था जिससे विदेशी मुद्रा भंडार 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के महत्वपूर्ण बिन्दु को पार करके 31 दिसम्बर, 2021 को 633.6 बिलियन स्तर को छू गया। नवम्बर, 2021 के अंत में भारत चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश था।[12,13]

विनियम दर में गतिविधि के मुद्दे के बारे में आर्थिक समीक्षा यह दर्शाती है कि रुपये ने अप्रैल-दिसम्बर, 2021 के दौरान अमेरिकी डॉलर की तुलना में दोनों दिशाओं में गतिविधि दर्शायी हैं फिर भी मार्च, 2021 की तुलना में दिसम्बर, 2021 में रुपये का 3.4 प्रतिशत अवमूल्यन हुआ। तथापि उभरते हुए बाजार दिग्गजों की तुलना में रुपये का अवमूल्यन बहुत कम रहा और यूरो, जापानी येन और पौण्ड स्टर्लिंग के सापेक्ष इसमें मजबूती रही।

विदेशी ऋण

सितम्बर, 2021 के अंत में भारत का विदेशी ऋण 593.1 बिलियन डॉलर था जो जून, 2021 के अंत के स्तर पर 3.9 प्रतिशत से अधिक था। आर्थिक समीक्षा यह दर्शाती है कि मार्च, 2021 के अंत में भारत के विदेशी ऋण ने पूर्व-संकट स्तर को पार कर लिया था यह सितम्बर, 2021 के अंत में एनआरआई जमाराशियों से पुनरुत्थान की मदद और अतंर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वन-ऑफ अतिरिक्त एसडीआर आवंटन की मदद से दढ़ हो गया। कुल विदेशी ऋण में लघु अवधि ऋण की हिस्सेदारी में थोड़ी सी गिरावट आयी। यह हिस्सेदारी जो मार्च, 2021 के अंत में 17.7 प्रतिशत थी सितम्बर के अंत में 17 प्रतिशत हो गई। समीक्षा यह दर्शाती है कि मध्यम अवधि परिप्रेक्ष्य से भारत का विदेशी ऋण उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था के लिए आंके गए इष्ट्रतम ऋण से लगातार कम चल रहा है।

भारत की समुत्थान शक्ति (लचीलापन) आर्थिक समीक्षा यह दर्शाती है कि भंडार में भारी बढ़ोतरी से विदेशी मुद्रा भंडारों से कुल विदेशी ऋण, लघु अवधि ऋण से विदेशी विनिमय भंडार जैसे बाह्य संवेदी सूचकांकों में सुधार को बढ़ावा मिला। बढ़ते हुए मुद्रा स्फीति दबावों की प्रतिक्रिया में फेड सहित प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण केन्द्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति के तेजी से सामान्यीकरण की संभावना से पैदा हुई वैश्विक तरलता की संभावना का सामना करने के लिए भारत का बाह्य क्षेत्र लचीला है।[14]

संदर्भ

[1] भारतीय अर्थव्यवस्था - एम के मिश्र एवं वी . के . पुरी , lopment हिमालया पब्लिशिंग हाऊस नई दिल्ली 2001

- [2] आर्थिक विकास एवं नियोजन एस . पी . सिंह , एस . चन्द एंड कम्पनी लि . रामनगर नई दिल्ली ,
- [3] आर्थिक विकास एवं नियोजन वी . सी . सिन्हा एवं आर . एन . दुबे मयूर पेपर बॉक्स ए - 95 सेक्टर - 5 नोएडा 231331
- [4] विकास का अर्थशास्त्र एम . एल झिंगन 149 मेन शकरपुरा मार्ग दिल्ली 92
- [5] अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एम . एल झिंगन कोर्णाक पब्लिकेशन प्रा . लि . ए - 149 मेन विकास मार्ग दिल्ली 110092
- [6] अर्थशास्त्र डॉ. जीवन लाल भारद्वाज , रामप्रसाद एंड संस भोपाल
- [7] प्रमुख आर्थिक सुधारों का विशलेषण डॉ. जे . पी . मिश्रा (प्रसास प्रकाशन)
- [8] दिशा दर्शन शोध पत्रिका 2015
- [9] भारतीय अर्थव्यवस्था रूद्र दत्त एवं के . पी . सुन्दयम
- [10] दृष्टि द विजन दृष्टि द विजन फांउडेशन 641 फस्टफयोर मुखर्जी नगर - दिल्ली 110009
  - [11] icsias.com
  - [12] india.com
- in [13] lindiagktoday.com
- ar[14] ndtv.com